tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

फीफा विश्व कप 2026 में नॉकआउट की तस्वीर साफ
Page-04

'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में शामिल
Page-05

सदी का सबसे भयानक भूकंप
164 मौतें, सैकड़ों घायल

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने गुरुवार सुबह एक अपडेट में बताया कि विनाशकारी भूकंपों के बाद मरने वालों की संख्या कम से कम 164 हो गई है, जबकि 971 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। CNN के अनुसार, अधिकारियों को डर है कि मरने वालों की असल संख्या काफी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत सारी इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और इमरजेंसी टीमें खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। रोड्रिगेज ने बताया कि मुख्य दोहरे झटकों के बाद इस इलाके में कम से कम 30 आफ्टरशॉक (बाद के झटके) महसूस किए गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला के सरकारी ब्रॉडकास्टर के साथ एक इंटरव्यू में रोड्रिगेज ने कहा कि वह बचाव टीमों को तैनात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ तालमेल बिठा रही हैं। वह देश के पुनर्निर्माण के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शुरुआती फंड बनाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के साथ भी बातचीत कर रही हैं। गुरुवार तड़के (भारतीय मानक समय के अनुसार) वेनेजुएला में लगातार दो ज़बरदस्त भूकंप आए, जिनसे राजधानी काराकस में भारी तबाही हुई और कई इमारतें ढह गईं। अधिकारियों और निगरानी एजेंसियों के अनुसार, ये दो भूकंप पिछले सौ सालों में इस लैटिन अमेरिकी देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप थे।U S जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के आंकड़ों से पता चला कि पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था और यह ज़मीन से 13 किलोमीटर की कम गहराई पर आया था। इसका केंद्र काराकस से लगभग 168 किलोमीटर पश्चिम में स्थित तटीय इलाके 'मोरोन' के पश्चिम में था। इसके ठीक 40 सेकंड बाद, उसी इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर 7.5 तीव्रता का और भी ज़्यादा ज़बरदस्त भूकंप आया। इसका केंद्र मोरोन से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था, जिससे प्रभावित इलाकों में तबाही और बढ़ गई। भूकंप की इस ज़बरदस्त गतिविधि के बाद, US पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड्स के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की, हालांकि बाद में ये चेतावनियां वापस ले ली गईं।

वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 164 लोगों की मौत और 971 लोग घायल हुए हैं।कई इमारतें ढह गई हैं, 30 से अधिक आफ्टरशॉक आ चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

अपने बयानों पर सफाई देते हुए सना मलिक ने कहा-बयानों का गलत मतलब निकाला गया

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि NCP (अजित पवार) की विधायक सना मलिक ने बहुविवाह का समर्थन किया और भारत में पाकिस्तानी कानून लागू करने की वकालत की। इस दावे से काफी बहस छिड़ गई और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अपने बयानों पर सफाई देते हुए मलिक ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर महाराष्ट्र विधानसभा में हुई बहस के दौरान उनके बयानों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि उनकी आपत्तियां महिलाओं की सुरक्षा और तीन तलाक पर चर्चा के दौरान बार-बार पाकिस्तान का ज़िक्र किए जाने तक ही सीमित थीं। मलिक ने कहा कि बहस महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर केंद्रित होनी चाहिए और ऐसे मुद्दों को सीधे किसी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सवाल उठाया गया था कि क्या पाकिस्तान ने कोई कानून बनाया है और चर्चा के दौरान पाकिस्तान का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर यह तर्क दिया कि कानून बनाने वालों को बहस में पाकिस्तान को लाने के बजाय खुद कानून पर चर्चा करनी चाहिए। मलिक के अनुसार, भारतीय मुसलमान भारतीय संविधान का पालन करते हैं, जो उन्हें अपने धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुलना स्वीकार्य नहीं है और पड़ोसी देश का बार-बार ज़िक्र किए जाने पर आपत्ति जताई।

2030 में सिर्फ़ भाजपा सदस्यता कार्ड धारकों को ही भारतीय नागरिक माना जाएगा-असदुद्दीन ओवैसी

एआईएमआईएम नेता ने सरकार के लंबे समय के एजेंडे पर गहरा शक जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों की नागरिकता की स्थिति को मनमाने ढंग से चुनौती देने की ताकत हासिल करना चाहता है। इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की संभावना पर तीखी टिप्पणी करते हुए ओवैसी ने कहा कि हो सकता है कि सरकार यह कह रही हो कि 2030 में सिर्फ़ उन्हीं लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनके पास BJP का मेंबरशिप कार्ड होगा। ओवैसी ने 1967 के पासपोर्ट एक्ट का ज़िक्र करते हुए नागरिकता के सबूत के तौर पर पासपोर्ट की वैधता पर बात की। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज़ कड़ी पुलिस जांच के बाद ही जारी किया जाता है, जो यह पक्का करता है कि इसे रखने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ़ भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। अगर आप पासपोर्ट एक्ट 1967 पढ़ेंगे, तो उसमें साफ़ लिखा है कि पासपोर्ट किसी गैर-भारतीय नागरिक को नहीं दिया जाता और यह पूरी पुलिस जांच के बाद ही दिया जाता है। फिर, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ़ नागरिकता का सर्टिफ़िकेट ही सबूत है, तो नागरिकता का सर्टिफ़िकेट तो सिर्फ़ उन लोगों को मिलता है जिन्हें रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइज़ेशन के ज़रिए नागरिकता मिली हो।

राम मंदिर दान विवाद में बड़ा मोड़: SIT रिपोर्ट के बाद FIR और गिरफ्तारी की तैयारी

अयोध्या राम मंदिर दान मामले में जांच अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके आधार पर जल्द ही FIR दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं जिन पर मंदिर को प्राप्त दान राशि के कथित दुरुपयोग या हेराफेरी में शामिल होने का आरोप है।जांच का मुख्य केंद्र राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के प्रबंधन और उसके उपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि दान राशि के संग्रह, गिनती और प्रबंधन की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं, जिससे धन के गलत इस्तेमाल की आशंका पैदा हुई। इन आरोपों की सत्यता की जांच के लिए SIT ने पिछले छह दिनों तक अयोध्या में रहकर मंदिर परिसर और संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत निरीक्षण किया। टीम ने कई अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित पक्षों से पूछताछ कर आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए।रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब FIR दर्ज होने और आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां जल्द ही आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं।इस बीच, विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि केवल आंतरिक जांच पर्याप्त नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष पुलिस जांच होनी चाहिए। VHP अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देशभर के श्रद्धालुओं ने भगवान राम के प्रति आस्था और विश्वास के साथ करोड़ों रुपये का दान दिया था। ऐसे में यदि दान राशि में किसी प्रकार की हेराफेरी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना आवश्यक है।राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई को लेकर समाज और विभिन्न संगठनों की नजरें सरकार तथा जांच एजेंसियों पर टिकी हुई हैं।

समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट की अटकलें

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के भीतर जल्द बड़ी फूट पड़ने का दावा कर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता वर्तमान नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं और आने वाले समय में पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संभावित बागी गुट का नेतृत्व पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रभावशाली नेता कर सकता है।राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर मतभेदों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी के निर्णयों और संगठनात्मक ढांचे से असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। समाजवादी पार्टी ने राजभर के आरोपों को गंभीरता से लेने से इनकार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और विपक्षी दलों द्वारा जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा रहा है।

अकाल तख्त का बड़ा आदेश: पंजाब के सभी सिख विधायक और मंत्री 29 जून को तलब

सिख धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था, अकाल तख्त ने पंजाब के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया है। साथ ही, गैर-सिख विधायकों और मंत्रियों को 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट, 2026' पर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इस कानून में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के अपमान के लिए उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान है। यह कदम पंजाब विधानसभा द्वारा 13 अप्रैल को उस कानून को पारित करने के कुछ महीनों बाद उठाया गया है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के मामलों में उम्रकैद और भारी जुर्माने जैसी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इस समन में पूरे पंजाब के 78 सिख विधायक, नौ सिख कैबिनेट मंत्री और भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार के पांच गैर-सिख कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। निर्देशों के अनुसार, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां सहित सभी 78 सिख विधायकों और नौ सिख कैबिनेट मंत्रियों को सुबह 11 बजे अकाल तख्त के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि गैर-सिख मंत्रियों और विधायकों को उसी तारीख तक लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। यह समन सभी पार्टियों के विधायकों को जारी किए गए हैं, जिनमें कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह, कांग्रेस नेता परगट सिंह, AAP मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरजोत सिंह बैंस, बलबीर सिंह और गुरमीत सिंह खुडियां के अलावा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां शामिल हैं। गैर-सिख मंत्रियों संजीव अरोड़ा, अमन अरोड़ा, वरिंदर कुमार गोयल, लाल चंद कटारूचक और महिंदर भगत को लिखित जवाब देने के लिए कहा गया है। अकाल तख्त सचिवालय के प्रभारी बगीचा सिंह ने बताया कि पंजाब विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद संपर्क विवरण के आधार पर, 17 और 18 जून को सिख विधायकों और मंत्रियों को उनके ईमेल पते और व्हाट्सएप नंबर पर आधिकारिक पत्र भेजे गए थे।

हिन्दी जगत महामंच
www.tvbharatvarsh.in
tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर
प्रदेश का नं. 1
प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़
ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2-3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

ट्रंप प्रशासन ने मांगे 87.6 अरब डॉलर

ईरान युद्ध और रक्षा जरूरतों पर बढ़ा फंडिंग दबाव

सैन्य खर्च के अलावा, इस प्रस्ताव में खेती-बाड़ी में मदद के लिए 11.1 अरब डॉलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, युगांडा और अफ़्रीका के दूसरे हिस्सों में इबोला के प्रकोप से निपटने की कोशिशों के लिए 1.4 अरब डॉलर की मांग भी की गई है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 24 जून को कांग्रेस से ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 87.6 अरब डॉलर की फ़ंडिंग का अनुरोध किया है। इस फ़ंडिंग का ज़्यादातर हिस्सा पेंटागन ने ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए मांगा है। इस प्रस्ताव में मध्य अफ़्रीका में इबोला से निपटने के प्रयासों और अमेरिकी किसानों के लिए वित्तीय सहायता के लिए भी पैसे शामिल हैं। प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने एक बयान में कहा कि हम सैनिकों के हित में इसे पास कराने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने और यह पक्का करने के लिए उत्सुक हैं कि हम आज किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। युद्ध विभाग ने 67 अरब डॉलर की धनराशि की मांग की है, जिसमें हथियारों के लिए 21 अरब डॉलर, ऑपरेशनल खर्चों के लिए 17.3 अरब डॉलर और गोपनीय कार्यक्रमों के लिए 12.1 अरब डॉलर शामिल हैं। पेंटागन ने कहा है कि उसे युद्ध और ईरान की परमाणु क्षमताओं से जुड़े ऊर्जा विभाग के लिए 76.75 करोड़ डॉलर की ज़रूरत है। इसने ईरान के आस-पास के देशों में दूतावास की सुरक्षा और निर्माण कार्य के लिए विदेश विभाग को 30 करोड़ डॉलर देने का भी ज़िक्र किया है। यह घटनाक्रम व्हाइट हाउस के लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल समय में हुआ है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के आर्थिक असर को लेकर बढ़ती चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। सांसदों पर भी युद्ध से जुड़े खर्च को सही ठहराने का भारी दबाव है। डेमोक्रेट्स ने पहले ही इस प्रस्ताव की आलोचना की है; उनका तर्क है कि मांगी गई ज़्यादातर फंडिंग की समीक्षा इमरजेंसी कानून के बजाय सामान्य बजट प्रक्रिया के ज़रिए की जानी चाहिए। सीनेट में माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने अतिरिक्त फंड की मांग पर कहा कि अमेरिका को एक गैर-जिम्मेदाराना युद्ध में धकेलने के बाद, अब वे चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए और अरबों डॉलर दे – जबकि परिवारों को अभी भी ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। सीनेट एप्रोप्रिएशन कमिटी में डेमोक्रेट्स की प्रमुख नेता और वॉशिंगटन की सीनेटर पैटी मरे ने इस मांग को पेंटागन की ऐसी प्राथमिकताओं के लिए अरबों डॉलर और हासिल करने की कोशिश" बताया, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इन फंड्स पर "सही तरीके से सालाना बजट आवंटन प्रक्रिया के तहत विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा मैं इस पूरी मांग की बारीकी से समीक्षा करूंगी और यह पक्का करूंगी कि हम अपने सैनिकों का ध्यान रखें, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से शुरू की गई इस विनाशकारी जंग के लिए अरबों डॉलर और मंज़ूर नहीं करूंगी। इस प्रस्ताव का बचाव करते हुए, सीनेट आर्म्ड सर्विसेज़ कमिटी के चेयरमैन और मिसिसिपी के GOP सीनेटर रोजर विकर ने कहा कि यह फंडिंग "ज़रूरी" है। उन्होंने कहा कि इससे खास तरह के गोला-बारूद से लेकर कम लागत वाले हाइपरसोनिक हथियार, स्ट्राइक हथियार और ड्रोन जैसी अहम क्षमताओं का तुरंत उत्पादन तेज़ी से हो सकेगा।

किंग चार्ल्स III अपने पर्सनल टैक्स बिल का खुलासा करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट बनेंगे

किंग चार्ल्स III गुरुवार को अपने पर्सनल टैक्स बिल का खुलासा करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट बनेंगे। बकिंघम पैलेस 'सॉवरेन ग्रांट' पर अपनी सालाना ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी जारी करेगा। यह कदम शाही परिवार के कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता की बढ़ती मांगों के बीच उठाया जा रहा है, खासकर उनके छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर के मामलों की महीनों तक हुई जांच-पड़ताल के बाद। चार्ल्स ने पहले भी अपनी पर्सनल इनकम पर दिए गए टैक्स की जानकारी दी थी जब वह प्रिंस ऑफ़ वेल्स थे, लेकिन 2022 में महारानी एलिज़ाबेथ II के निधन के बाद राजा बनने के बाद यह पहली बार होगा जब वह ऐसा करेंगे। उम्मीद है कि मौजूदा प्रिंस ऑफ़ वेल्स, प्रिंस विलियम भी एक अलग ब्रीफिंग में इसी तरह का तरीका अपनाएंगे। सालाना ब्रीफ़िंग में 'सॉवरेन ग्रांट' (शाही अनुदान) के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जिसके ज़रिए टैक्स देने वाले लोग राजशाही को फ़ंड देते हैं। पिछले साल बकिंघम पैलेस ने 159 पेज की एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि ट्रेज़री से मिले 8.63 करोड़ पाउंड (86.3 मिलियन पाउंड) कैसे खर्च किए गए, जिसमें महल की बड़ी मरम्मत पर खर्च हुआ पैसा भी शामिल था। यह नया कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सांसद और आम लोग राजशाही के कामकाज के बारे में ज़्यादा पारदर्शिता चाहते हैं, खासकर पूर्व प्रिंस एंड्रयू से जुड़े खुलासों के बाद, जिनसे 2025 में उनके शाही खिताब छीन लिए गए थे। अब एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर के नाम से पहचाने जाने वाले एंड्रयू पर, दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अपनी दोस्ती से जुड़े सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत व्यवहार के लिए जांच चल रही है। उन्हें एक बड़ी शाही जागीर भी छोड़नी पड़ी है, जहाँ वे बिना किराया दिए रह रहे थे। बीबीसी के अनुसार, महल के सूत्रों का कहना है कि राजा ने "बेहतर समझ और जवाबदेही को बढ़ावा देने" की कोशिश के तहत अपने टैक्स भुगतान का खुलासा करने का व्यक्तिगत निर्णय लिया।

देश की सुरक्षा को नई ताकत 'नेत्रा' अब पूरी तरह ऑपरेशनल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश की सुरक्षा को नई ताकत देने वाली 'नेत्रा' अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई है। आसमान में उड़ती यह स्वदेशी आंख दुश्मन की हर गतिविधि पर दूर से नजर रख सकती है और भारतीय वायुसेना को रियल-टाइम इंटेलिजेंस उपलब्ध कराती है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सेंटर फॉर एयर बॉर्न सिस्टम्स CABS में विकसित स्वदेशी टोही और निगरानी विमान नेत्रा अवॉक्स को आज फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेन्स यानी FOC मिल गया। इसका मतलब ये है कि बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली आसमान में हमारी आंख "नेत्रा" अब पूरी तरह से वायु सेना को और सशक्त बनाने के लिए तैयार है। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में उप वायु सेना प्रमुख अवधेश भारती ने FOC सर्टिफिकेट रिसीव किया और नेत्रा को प्रमाणित रूप से वायु सेना के बेड़े में शामिल करने की घोषणा की। एफओसी वह अंतिम चरण होता है, जिसमें किसी विमान या सैन्य प्रणाली को सभी जरूरी परीक्षणों और मानकों को पूरा करने के बाद पूरी तरह से मिशन के लिए तैयार घोषित किया जाता है। यह संचालन की प्रारंभिक मंजूरी (आईओसी) के बाद आता है। vAEW&C यानी Airborne Early Warning and Control नेत्रा भारत द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक हवाई निगरानी एवं कमांड-एंड-कंट्रोल प्रणाली है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की CABS लैब में बनाया गया है। यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का लंबी दूरी से पता लगाने और उनकी निगरानी करने में सक्षम है। 'नेत्रा' केवल निगरानी ही नहीं करती, बल्कि वास्तविक समय में वायुसेना के लड़ाकू विमानों और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध कराती है, जिससे युद्ध के दौरान त्वरित और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है।

ईरान बातचीत में अमेरिका की शर्तें मान रहा होर्मुज शुल्क पर कड़ा रुख

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नया पैंतरा दिखाया है। ट्रंप ने अब दावा किया है कि, ईरान चल रही बातचीत में अमेरिका की सभी शर्तें मान रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी साफ किया कि अमेरिका भविष्य में ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिससे ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली शिपिंग पर शुल्क लगाने की इजाज़त मिले। ट्रंप ने ये दावा भी किया कि ईरान अब होर्मुज में शिपिंग फीस भी नहीं लेगा। इसके साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कूटनीति नाकाम रहती है, तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला है। वॉशिंगटन में कई कार्यक्रमों में बोलते हुए, जिनमें कैपिटल में रिपब्लिकन सांसदों के साथ और बाद में व्हाइट हाउस में NATO महासचिव मार्क रुटे के साथ बैठकें शामिल थीं, ट्रंप ने ईरान के साथ हो रही बातचीत को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "ईरान के साथ हुए युद्ध में हम बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। अब तो ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह बहुत, बहुत, बहुत असरदार रहा है और सब कुछ बहुत, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है।" नाटो (NATO) के महासचिव मार्क रुटे के साथ ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान, ट्रंप ने किसी भी ऐसे समझौते की संभावना को खारिज कर दिया जिससे ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की अनुमति मिले। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी कोई शर्त अंतिम समझौते को प्रभावित करेगी, तो उन्होंने जवाब दिया, "हां, यह मुझे मंजूर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कई जलडमरूमध्य हैं; अगर आप उनके लिए ऐसा करते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी ऐसा करना होगा... मैं वहां भी इसकी अनुमति नहीं दूंगा। हां, यह एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम (गेम चेंजर) होगा।" ट्रंप से ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हुए हमले की जांच के बारे में भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे पता चले कि हमले में अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। ट्रंप ने कहा, "नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि वे कभी इस मामले को सुलझा पाएंगे... क्योंकि उस समय हर तरफ मिसाइलें चल रही थीं।

वेनेजुएला में भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

वेनेजुएला में भूकंप के दो जबरदस्त झटकों ने बुधवार को भारी तबाही मचाई है। इससे कई इमारतें ढह गईं हैं, जिसमें दबकर अब तक 164 लोगों की जान चली गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में बुधवार सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके एक मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। काराकस में इमारतों के गिरने के बाद 700 लोग घायल हुए हैं। जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, यह सैंकड़ों तक जा सकती है। वहीं, घायलों की संख्या 10 हजार तक पहुंच सकती है। बता दे कि इससे पहले काराकस में जोरदार भूकंप साल 1967 में आया था। तब इमारतों के गिरने से 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। बताया जाता है कि काराकास में 29 जुलाई, 1967 को लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी। सिर्फ 35 सेकंड में शहर की कई ऊंची इमारतें धड़ाम से गिर गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गए। ये भूकंप वेनेजुएला के इतिहास में एक बड़ा सदमा माना जाता है। आज जब वेनेजुएला में नया भूकंप आया है तो लोग 1967 की उस रात को याद कर रहे हैं। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन से जुड़ी संस्था के अनुसार उस भूकंप में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 225 से 300 तक बताया गया है। इसमें करीब 1500 लोग घायल हुए। ज्यादातर मौतें आधुनिक ऊंची इमारतों के गिरने से हुईं। अल्तामिरा और लॉस पालोस ग्रांदेस जैसे इलाकों में तबाही सबसे ज्यादा थी। यह भूकंप शाम 8 बजे आया था, तब लोग घरों में खाना खा रहे थे या टीवी देख रहे थे। अचानक सब कुछ हिलने लगा। लोग चीखते-चिल्लाते बाहर भागे। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम दिन-रात काम करती रही। इसमें संपत्ति का नुकसान करीब 5 से 14 करोड़ डॉलर का हुआ। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। सरकार को नई इमारतों के लिए सख्त नियम बनाने पड़े।

संपादक की कलम से

क्या पश्चिम एशिया शांति की ओर बढ़ रहा है?पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक वार्ताओं ने दुनिया को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है। लंबे समय से तनाव, प्रतिबंधों और सैन्य टकरावों से जूझ रहे इस क्षेत्र में यदि स्थायी शांति स्थापित होती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा।हाल के दिनों में अमेरिकी प्रशासन ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात को लेकर भी सहमति बनने की संभावना है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करता है। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए इस क्षेत्र में स्थिरता अत्यंत आवश्यक है।हालांकि, केवल बातचीत शुरू हो जाना ही स्थायी समाधान की गारंटी नहीं है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास की गहरी खाई रही है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव, प्रतिबंध और सुरक्षा संबंधी चिंताएं अब भी दोनों देशों के बीच प्रमुख विवादों के विषय हैं। ऐसे में किसी भी समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक शांति को प्राथमिकता देते हैं या नहीं।दूसरी ओर, युद्ध से जुड़े बढ़ते सैन्य खर्चों ने अमेरिका के भीतर भी बहस छेड़ दी है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा युद्ध संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त फंडिंग की मांग ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या सैन्य समाधान वास्तव में स्थायी शांति ला सकते हैं, या फिर कूटनीति ही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है।विश्व समुदाय को यह समझना होगा कि आधुनिक युग में युद्ध किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। संघर्ष चाहे कितना भी जटिल क्यों न हो, संवाद और कूटनीति ही स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पश्चिम एशिया को आज हथियारों की नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और संवाद की आवश्यकता है। यदि अमेरिका और ईरान इस दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, तो यह न केवल क्षेत्र बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।

'संविधान हत्या दिवस' पर देशभर में भाजपा के कार्यक्रम

कांग्रेस के साथ छिड़ी नई सियासी जंग

कांग्रेस ने भाजपा के कार्यक्रमों को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार स्वयं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बना रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पार्टी का कहना है कि भाजपा को इतिहास की बजाय वर्तमान चुनौतियों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और आर्थिक मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की 51वीं बरसी गुरूवार को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर इतिहास के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। आपातकाल की बरसी को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में तीखी बयानबाजी देखने को मिली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर संदेश जारी कर उन सभी लोगों को नमन किया, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है, जब देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को इस दौर के बारे में अवश्य जानना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।भाजपा ने इस मौके पर देशभर में संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों, प्रदर्शनियों और जनसभाओं का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आपातकाल भारतीय संविधान की मूल भावना पर सीधा प्रहार था। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया था।उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश ने लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का दौर देखा था और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों का योगदान सदैव याद रखा जाएगा।वहीं कांग्रेस ने भाजपा के कार्यक्रमों को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार स्वयं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बना रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पार्टी का कहना है कि भाजपा को इतिहास की बजाय वर्तमान चुनौतियों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और आर्थिक मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के चुनावों को देखते हुए आपातकाल का मुद्दा आने वाले दिनों में भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बना रह सकता है। भाजपा जहां इसे कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल के रूप में जनता के सामने रख रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति बता रही है। ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासी संघर्ष और तेज होने की संभावना है।

एनसीईआरटी की नई किताबों में आपातकाल अध्याय पर छिड़ा सियासी संग्राम

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में आपातकाल से जुड़े अध्यायों को प्रमुखता दिए जाने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। 25 जून को आपातकाल की 51वीं बरसी के बीच इस मुद्दे ने देश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास बताया है, जबकि कांग्रेस ने शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है।एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों में वर्ष 1975 में लागू किए गए आपातकाल, उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़े प्रभाव का विस्तार से उल्लेख किया गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि लंबे समय तक देश के छात्रों को इस विषय की पूरी जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि नई शिक्षा सामग्री से विद्यार्थियों को लोकतंत्र के महत्व और संवैधानिक मूल्यों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना जरूरी था। पार्टी का दावा है कि इससे युवा पीढ़ी देश के राजनीतिक इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकेगी और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति जागरूक होगी।दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इतिहास को अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों को संतुलित और तथ्यपरक इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतिहास के संवेदनशील विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है, लेकिन उनकी प्रस्तुति निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को मजबूत करने में सहायक साबित हो सकती है।

गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक स्वच्छ ऊर्जा सहयोग पर जोर

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत की मेजबानी में गुरुग्राम में गुरुवार से ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।बैठक का मुख्य फोकस सदस्य देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को साझा करने और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत बनाने पर है। वर्तमान समय में दुनिया ऊर्जा संक्रमण के दौर से गुजर रही है और अधिकांश देश पारंपरिक ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है।भारत ने बैठक के दौरान हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को भी साझा किया। भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की वकालत करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका वैश्विक ऊर्जा नीति में उसकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।बैठक में सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग, निवेश बढ़ाने और ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। बैठक के समापन पर साझा घोषणा-पत्र जारी किए जाने की संभावना है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लिए भविष्य की रूपरेखा तय की जा सकती है।

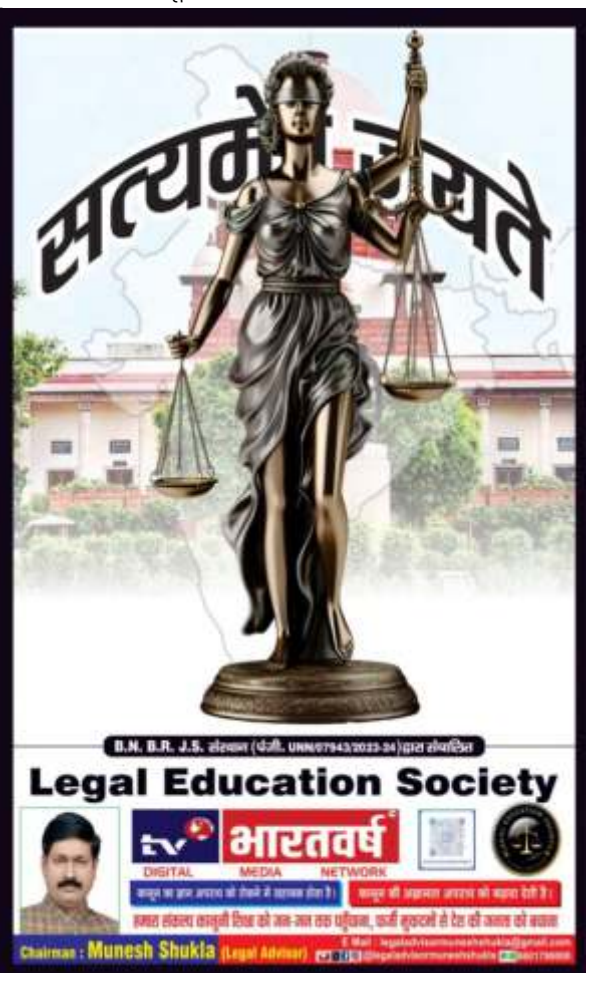

सीयूईटी-यूजी 2026 के नतीजों के बाद

विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया तेज,छात्रों में बढ़ी हलचल

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी) 2026 के परिणाम जारी होने के बाद देशभर के केंद्रीय और अन्य भागीदारी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया तेज हो गई है। लाखों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की दिशा तय करने वाली इस परीक्षा के नतीजे घोषित होने के साथ ही अब विश्वविद्यालयों ने काउंसलिंग, पंजीकरण और सीट आवंटन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिणाम जारी होने के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच उत्साह के साथ-साथ अपने पसंदीदा संस्थान में प्रवेश को लेकर उत्सुकता भी बढ़ गई है।राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सीयूईटी-यूजी परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया सहित अनेक प्रमुख शिक्षण संस्थानों ने अपनी प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है।दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) पोर्टल के माध्यम से दाखिले की प्रक्रिया को गति दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से समय पर पंजीकरण करने और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अपील की है। इसी प्रकार अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी अपनी-अपनी प्रवेश संबंधी अधिसूचनाएं जारी करनी शुरू कर दी हैं। कई विश्वविद्यालयों ने मेरिट सूची और सीट आवंटन की संभावित तिथियों की जानकारी भी साझा की है।शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीयूईटी प्रणाली लागू होने के बाद देशभर के छात्रों को एक समान अवसर मिला है। पहले विद्यार्थियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों की अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं देनी पड़ती थीं, लेकिन अब एक ही परीक्षा के आधार पर अनेक विश्वविद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिल रहा है। इससे छात्रों पर आर्थिक और मानसिक दबाव भी कम हुआ है।हालांकि विशेषज्ञों ने छात्रों को केवल प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम के आधार पर निर्णय लेने से बचने की सलाह दी है। उनका कहना है कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि, करियर संभावनाओं, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और संस्थान की शैक्षणिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही विषय और विश्वविद्यालय का चयन करना चाहिए।इस बीच, कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन सहायता केंद्र भी शुरू किए हैं ताकि उन्हें प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देशभर के लाखों छात्रों की निगाहें पहली सीट आवंटन सूची और काउंसलिंग प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं, जो आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा के नए सत्र की तस्वीर तय करेगी।

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा पर बढ़ा जोर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों ने स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारियां तेज कर दी हैं। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बाद विभिन्न राज्यों में विद्यालयों में व्यावसायिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक और व्यावहारिक ज्ञान से भी जोड़ना है।नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और कौशल विकास कार्यक्रमों से परिचित कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्कूलों में स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। छात्रों को कृषि, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बढ़ईगिरी, हस्तशिल्प, उद्यमिता और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों की जानकारी देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि बदलते समय में केवल सैद्धांतिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है। इसके तहत कई राज्यों में पायलट परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं, जहां विद्यार्थियों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है।विशेषज्ञों का कहना है कि कौशल आधारित शिक्षा से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी। इससे छात्र केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने से उच्च शिक्षा और उद्योग जगत के बीच की दूरी भी कम होगी।

साई सुदर्शन ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा धमाकेदार शतक

सिनर और जोकोविच पर रहेंगी दुनिया की निगाहें विंबलडन 2026 के लिए मंच तैयार

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2026 की शुरुआत 29 जून से होने जा रही है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टेनिस जगत में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इस बार भी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी खिताब जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। प्रशंसकों की सबसे ज्यादा निगाहें मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर और अनुभवी स्टार नोवाक जोकोविच पर टिकी हुई हैं।विश्व नंबर एक यानिक सिनर बतौर डिफेंडिंग चैंपियन इस टूर्नामेंट में उतरेंगे। पिछले वर्ष उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला विंबलडन खिताब जीता था। इस सत्र में भी सिनर बेहतरीन लय में नजर आए हैं और कई बड़े टूर्नामेंट अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें इस बार भी खिताब का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है।दूसरी ओर, 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में कोर्ट पर उतरेंगे। जोकोविच विंबलडन में अब तक सात बार खिताब जीत चुके हैं और उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, हाल के महीनों में चोटों के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित रहा है, लेकिन बड़े टूर्नामेंटों में वापसी करने की उनकी क्षमता किसी से छिपी नहीं है।इस बार जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, अमेरिका के बेन शेल्टन और टेलर फ्रिट्ज जैसे खिलाड़ी भी खिताब की दौड़ में शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि घास के कोर्ट पर इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन टूर्नामेंट को और रोमांचक बना सकता है। खासकर फ्रिट्ज को घास के कोर्ट का विशेषज्ञ माना जाता है और वे बड़े उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं।टेनिस प्रेमियों के लिए इस बार का विंबलडन कई मायनों में खास रहने वाला है। नए और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच होने वाली टक्कर टूर्नामेंट को रोमांचक बनाएगी। अब सभी की निगाहें 29 जून से शुरू होने वाले मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम गौरव के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे।

फीफा विश्व कप 2026 मेक्सिको और मोरक्को का दमदार प्रदर्शन

मेक्सिको सिटी। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप चरण के मुकाबले जैसे-जैसे अंतिम दौर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे टूर्नामेंट का रोमांच भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। गुरुवार को खेले गए अहम मुकाबलों में मेक्सिको और मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट चरण में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। दोनों टीमों की जीत ने उनके प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है और खिताब की दौड़ को और रोचक बना दिया है।मेजबान देशों में शामिल मेक्सिको ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार खेल दिखाया। टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और पूरे मैच के दौरान विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। मेक्सिको की जीत के बाद स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने जश्न मनाया। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू परिस्थितियों का फायदा मेक्सिको को आगे के मुकाबलों में भी मिल सकता है।दूसरी ओर, मोरक्को ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत विश्व कप में लगातार प्रभाव छोड़ा है। पिछली बार की तरह इस बार भी टीम ने अनुशासित खेल का प्रदर्शन करते हुए मजबूत दावेदारी पेश की है। मोरक्को की रक्षापंक्ति और तेज आक्रमण विपक्षी टीमों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। टीम के खिलाड़ियों ने सामूहिक प्रदर्शन के दम पर जीत हासिल की और नॉकआउट की राह आसान कर ली।विश्व कप 2026 में इस बार कई पारंपरिक दिग्गज टीमों के साथ-साथ उभरती टीमें भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इससे टूर्नामेंट में बड़े उलटफेर की संभावनाएं बढ़ गई हैं। फुटबॉल विशेषज्ञों का कहना है कि नॉकआउट चरण में मुकाबले और अधिक रोमांचक होंगे, क्योंकि अब प्रत्येक मैच 'करो या मरो' की स्थिति वाला होगा।

फीफा विश्व कप 2026 में नॉकआउट की तस्वीर साफ

फीफा विश्व कप 2026 अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। ग्रुप चरण के मुकाबलों के अंतिम दौर के साथ ही नॉकआउट चरण की तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। गुरुवार को खेले गए अहम मुकाबलों में ब्राजील, मोरक्को, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको और बोस्निया-हर्जेगोविना जैसी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। विश्व कप के इस चरण में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ गया है।पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने स्कॉटलैंड के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए 3-0 की एकतरफा जीत दर्ज की। ब्राजील की ओर से विनीसियस जूनियर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे, जबकि एक अन्य गोल मैथियस कुन्हा के नाम रहा। इस जीत के साथ ब्राजील ने ग्रुप चरण का समापन शीर्ष स्थान पर करते हुए नॉकआउट में प्रवेश किया। टीम का आक्रमण और रक्षापंक्ति दोनों ही शानदार लय में नजर आए।दूसरी ओर, मोरक्को ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट चरण में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को हराकर अगले दौर का टिकट हासिल किया, जबकि मैक्सिको और बोस्निया-हर्जेगोविना ने भी अहम जीत दर्ज कर अपने प्रशंसकों को खुश होने का मौका दिया। कई टीमों के लिए अंतिम ग्रुप मुकाबले 'करो या मरो' की स्थिति वाले थे, जिसके चलते मैदान पर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। इस बार विश्व कप में कई युवा खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री ने भी दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के खेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है।

मनोरंजन-3

25 जून 2026

03

1 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में शामिल, शाहिद-कृति की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार

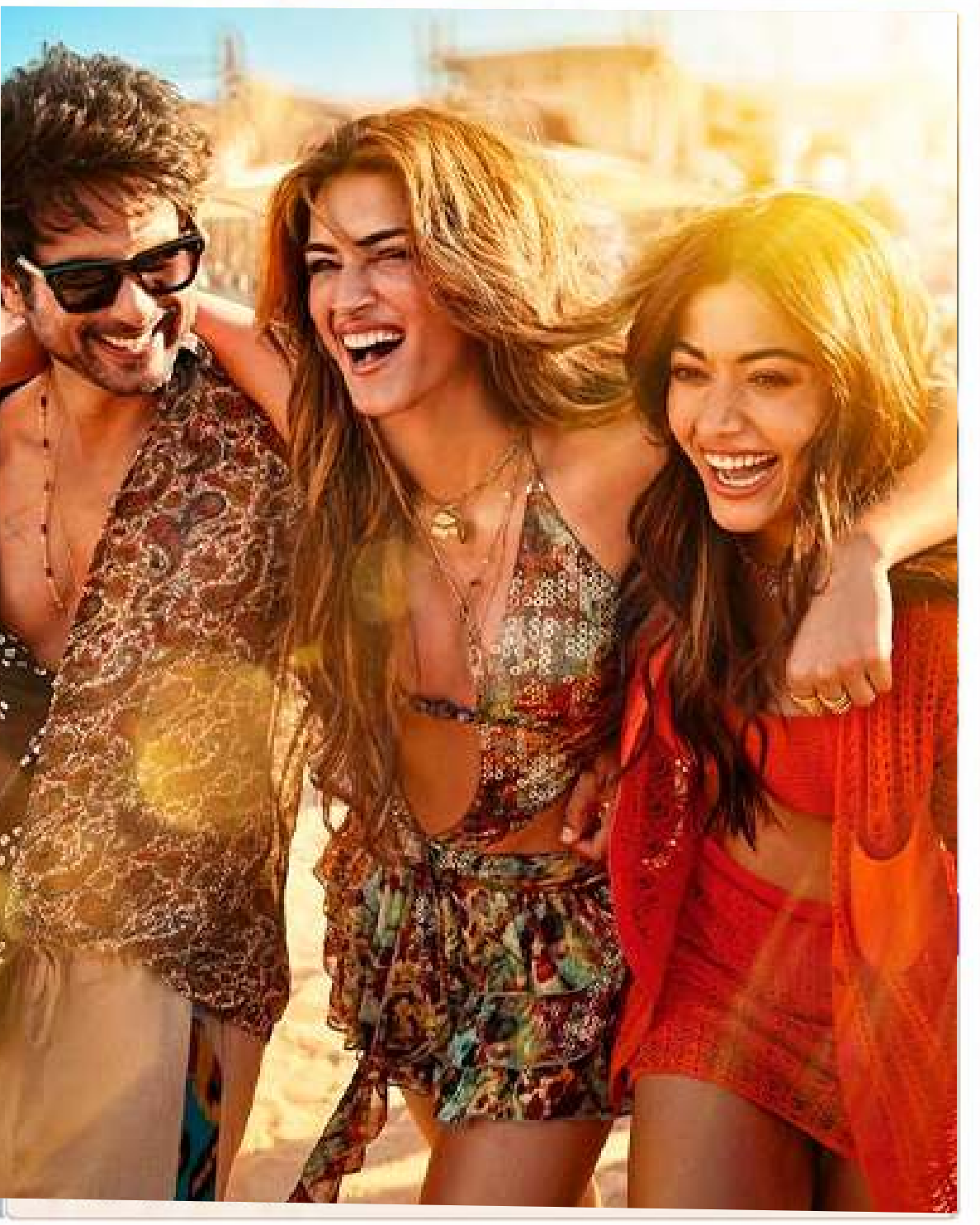

मुंबई । शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'कॉकटेल 2'ने बॉक्स ओफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले सप्ताह में ही दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। दर्शकों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण फिल्म सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है।

फिल्म को खासकर युवा दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। रोमांस, कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा के मिश्रण के साथ फिल्म की कहानी और संगीत को खूब सराहा जा रहा है। शाहिद कपूर और कृति सेनन की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, जबकि रश्मिका मंदाना ने भी अपने किरदार से सभी का दिल जीत लिया है।

फिल्म की रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर इसके गाने और संवाद लगातार ट्रेड कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि फिल्म की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो यह वर्ष 2026 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो सकती है।

2 शाहरुख खान का मुंबई इवेंट में दिखा खास अंदाज, पुराने हिट गानों पर किया डांस

मुंबई । बॉलीवुड़ सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर अपने खास अंदाज कों लेकर चर्चा में हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शाहरुख ने अपने लोकप्रिय गीत 'बादशाह ओ बादशाह' और 'चांद तारे' पर शानदार प्रस्तुति दी। दर्शकों ने उनके इस अंदाज को खूब सराहा।

कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान ने अपने प्रशंसकों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इन दिनों शाहरुख अपनी आगामी फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त हैं।

सोशल मीडिया पर उनके डांस और अंदाज के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रशंसक लगातार उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे है।

खास बातें

- शाहरुख ने 'बादशाह ओ वादशाह' और 'चाँद तारे' गाने पर डांस किया।
- मुंबई के एक इवेंट में हजारों फैंस के सामने की परफॉर्मेंस।
- शाहरुख इन दिनों फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त।
- उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल।
- फैंस ने कहा- 'वॉलीवुड का वादशाह हमेशा दिलों में राज करता है।'

3 '3 इडियट्स 2' को लेकर बढ़ी चर्चा, कहानी को लेकर सामने आई नई जानकारी

मुंबई । साल 2009 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुवाविक, '3 इडियट्स 2' की कहानी पहले भाग से कई साल आगे की दिखाई जा सकती है, जिसमें रैंचो, फरहान और राजु के किरदार वदलते हुए अंदाज में नजर आ सकते हैं।

आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी अभिनीत इस फिल्म ने वॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और यह हिंदी सिनेमा की सवसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है।

हालांकि, निर्माताओं की ओर से अभी तक कोआधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिल्म से जुड़ी हर छोटी जानकारी ने दर्शकों की उत्सुकता वढ़ा दी है। फैंस अव इसके आधिकारिक ऐलान का वेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म से जुड़ी अहम बातें

- '3 इडियट्स' ने वॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था।
- सीक्वल की कहानी में नई पीढ़ी की चुनोतियों को दिखाया जा सकता है।
- आमिर खान और माधवन की वापसी की चर्चा तेज।
- शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दों पर आधारित होगी कहानी।
- फैंस को आधिकारिक घोषणा का इंतजार।

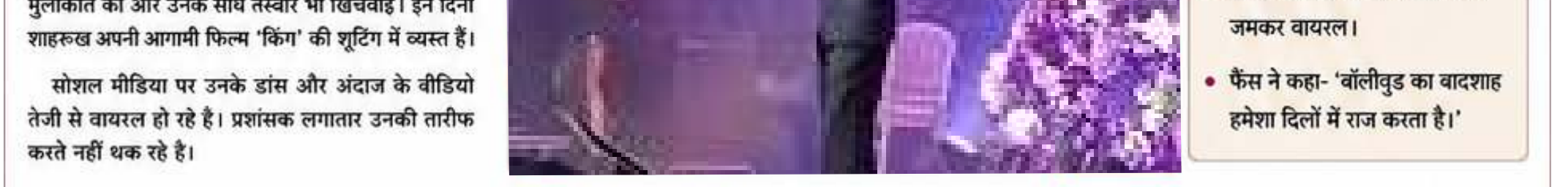

लखनऊ में संजय सिंह का बड़ा दावा,

"मेरे पास घोटाले से जुड़े पूरे रिकॉर्ड हैं"

AAP सांसद संजय सिंह एसआईटी के समक्ष पेश हुए और जमीन घोटाले से जुड़े 13 भूखंडों के दस्तावेज सौंपे। उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को जमीन घोटाले से जुड़े कथित मामलों के संबंध में विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश हुए। एसआईटी कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उनके पास कई अहम दस्तावेज और सबूत हैं, जिन्हें वह जांच एजेंसी को सौंपने आए हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि उनके पास करीब 13 भूखंडों से जुड़े दस्तावेज हैं, जिनमें 11 जमीनों के रिकॉर्ड और दो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में कथित घोटालों से जुड़ी जानकारी मौजूद है। एसआईटी कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा, "एसआईटी ने मुझे बुलाया है और मैं आज सभी सबूत उनके सामने पेश करने आया हूं। मेरे पास लगभग 13 भूखंडों से संबंधित दस्तावेज हैं। इन कागजात में घोटालों का पूरा विवरण है और मैं इन्हें जांच एजेंसी को सौंप रहा हूं।" संजय सिंह के एसआईटी के सामने पेश होने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जमीन से जुड़े कथित घोटालों का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा में है और अब मामले में नए दस्तावेज सामने आने के दावे ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रही है। ऐसे में संजय सिंह द्वारा एसआईटी को दस्तावेज सौंपने की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताओं के प्रमाण हैं तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। संजय सिंह ने जिन 13 भूखंडों से जुड़े दस्तावेजों का उल्लेख किया है, उन्हें लेकर अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर उत्सुकता बढ़ गई है। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर जमीन खरीद, हस्तांतरण और अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी शामिल है। हालांकि, अभी तक इन दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही एसआईटी की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत बयान जारी किया गया है। लेकिन संजय सिंह के दावों के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जांच एजेंसियों के जानकारों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मामले से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो जांच एजेंसी उन कागजात की सत्यता और प्रासंगिकता की गहन जांच करती है। एसआईटी अब संजय सिंह द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों का अध्ययन करेगी और आवश्यक होने पर संबंधित पक्षों से पूछताछ भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, यदि दस्तावेजों में प्रथम दृष्टया कोई अनियमितता सामने आती है तो जांच का दायरा और व्यापक हो सकता है। वहीं, जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल करेगी कि दस्तावेजों में किए गए दावे कितने तथ्यात्मक और प्रमाणिक हैं। आम आदमी पार्टी लंबे समय से विभिन्न मुद्दों पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करती रही है। संजय सिंह ने भी कहा कि वह जांच एजेंसी को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं और उनके पास जो भी दस्तावेज हैं, वे सभी जांच के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार का घोटाला हुआ है तो उसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

लखनऊ में तेज धूप और उमस ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

लखनऊ में मौसम साफ होने के साथ में तेज धूप से तपन और उमस भरी गर्मी बरकरार है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 61 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 35 फीसदी रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य में अभी कोई मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। इस वजह से तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है और आगामी 27 जून तक पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में लू का प्रकोप यूं ही बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 28 जून से प्रदेश में बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है, जो धीरे-धीरे और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है, और उसके अगले 2-3 दिनों में यह पूरे राज्य में आगे बढ़ जाएगा। जून के आखिरी हफ्ते में यूपी वालों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलने वाली है।

लखनऊ पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान,

मुख्यमंत्री योगी से की अहम बैठक

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को लखनऊ पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। बैठक में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, खरीफ सीजन की तैयारियों, जल संरक्षण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक रोडमैप तैयार करने पर विशेष फोकस रहा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल की वर्षगांठ पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए इसे संविधान हत्या दिवस बताया। लखनऊ पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इसके बाद वह निर्धारित कार्यक्रम के तहत कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी बैठकों में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की कृषि व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है और कृषि उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा, "आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ कृषि और ग्रामीण विकास पर व्यापक चर्चा होनी है। उत्तर प्रदेश कृषि में हमारा सिरमौर प्रदेश है। वर्तमान परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए कृषि के लिए वैज्ञानिक रोडमैप तैयार करना जरूरी हो गया है।" उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए नई तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाना समय की मांग है। इससे एक दिन पहले 24 जून को कृषि भवन, लखनऊ से केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में खरीफ सीजन-2026 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मानसून की संभावित चुनौतियों और मौसम में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए सूखा सहनशील बीजों के उपयोग, जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, डीएसआर तकनीक से धान की बुआई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दलहन उत्पादन बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

राजकीय, अनुदानित, पीपीपी और निजी पॉलीटेक्निक की कुल 1,20,984 सीटों पर होगा एडमिशन

उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों (फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर) की ऑनलाइन प्रवेश काउंसिलिंग आज यानी 25 जून से शुरू हो रही है। इसके लिए सभी राजकीय और अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों में सहायता केंद्र भी बनाया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया से प्रदेश के 365 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें 156 राजकीय, 18 अनुदानित, 29 पीपीपी मॉडल व 162 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाएं शामिल हैं। इनमें कुल 1,20,984 सीट हैं। संजीव सिंह ने बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में घोषित परिणाम में अर्ह अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। अभ्यर्थी समय सारणी के अनुसार काउंसलिंग पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं। इसे बाद संस्थान और पाठ्यक्रम में प्रवेश की संभावना देखकर अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपने जिले के राजकीय और अनुदानित पॉलीटेक्निक में बने सहायता केंद्रों पर जाकर काउंसिलिंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। काउंसिलिंग से जुड़ी समय-सारणी, दिशा-निर्देश और अन्य आवश्यक जानकारी परिषद की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध है।

लखनऊ के विभूति खंड में देर रात गोलीकांड, युवक घायल होकर अस्पताल में भर्ती

लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र में बुधवार देर रात विजयपुर के आगे किसान चबूतरा के पास गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला के रंजीतपुर सुनहरा निवासी मोनू शुक्ला उर्फ रोहित (25) मौजूदा समय में चिनहट क्षेत्र के विधायक चौराहा के पास रहता है। मोनू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका पिछले करीब 15 दिनों से सैफ, शान यादव, अक्सीर, सार्थक यादव, डेविड, लकी यादव समेत कुछ अन्य लोगों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि उन लोगों ने उसके हाथ में तमंचा देकर वीडियो और रील बनाई थी। जिसे वायरल करने की धमकी दे रहे थे। बुधवार रात मोनू किसान चबूतरा के पास पहुंचा था। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी बाइक से वहां आ गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान तमंचे को लेकर छीना-झपटी हुई। इस दौरान गोली चल गई, जो मोनू के दाहिने हाथ को छूते हुए जांघ में जा लगी। सूचना पर इंस्पेक्टर विभूतिखंड पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

अग्निकांड में जान गंवाने वाले बच्चों की याद में श्रद्धांजलि सभा

लखनऊ में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। अलीगंज अग्निकांड में जान गंवाने वाले बच्चों की याद में गुरुवार को सदर लखनऊ व्यापार मंडल की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 1090 चौराहे पर 101 पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देते समय कई लोगों की आंखें नम हो गईं। सदर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतबीर सिंह राजू के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उपस्थित लोगों ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। कई दिन गुजर जाने के बाद भी बच्चों की तस्वीर आंखों के सामने है। सतबीर सिंह राजू ने कहा कि इस भीषण हादसे में कई होनहार बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों का यूं असमय चले जाना पूरे समाज के लिए बड़ी क्षति है। सभी नागरिकों को पीड़ित परिवारों के दुख में सहभागी बनना चाहिए और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करना चाहिए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत बच्चों की आत्माओं को शांति मिले और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। श्रद्धांजलि के दौरान सुनील वैश (महामंत्री), विपिन वैश दयाल (मंत्री), संजय केसरवानी (मंत्री), रणवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

निर्जला एकादशी पर भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने दिया सामाजिक समरसता का संदेश,

जरूरतमंदों को वितरित की सहायता सामग्री

उन्नाव। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी अथवा भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, के पावन अवसर पर "नर सेवा-नारायण सेवा" समिति के संस्थापक एवं भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने समाज में सेवा, सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने शहर के मोचियों तथा अन्य जरूरतमंद परिवारों के बीच विभिन्न प्रकार की सहायता सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को मिट्टी के घड़े, खाद्य सामग्री, अंग वस्त्र तथा दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुएं सम्मानपूर्वक भेंट की गईं। भीषण गर्मी को देखते हुए मिट्टी के घड़ों का वितरण विशेष रूप से लोगों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया गया। सहायता प्राप्त करने वाले लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए समिति और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसी आध्यात्मिक भावना को सेवा और दान के माध्यम से समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से विमल द्विवेदी कई वर्षों से इस प्रकार के जनसेवा अभियान का संचालन कर रहे हैं। विमल द्विवेदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म में दान, सेवा और परोपकार का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक सम्मान और सहयोग पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज की सभी जातियां और वर्ग हिंदुत्व के मजबूत स्तंभ हैं तथा समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सेवा कार्य केवल जरूरतमंदों की सहायता तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य भी करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग और सद्भाव की भावना विकसित करना ही इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और समिति के सदस्य उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, अनीता विमल द्विवेदी, राकेश राजपूत, केतन अवस्थी, अभि तिवारी, राजेंद्र राजपूत, अमूल्य, विकास सिंह सेंगर, राघवेंद्र पांडेय, मनीष अवस्थी, धर्मेंद्र शुक्ल तथा परिमल मिश्रा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

उन्नाव में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, 1.56 करोड़ की संपत्ति कुर्क

उन्नाव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों की 1.56 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। प्रशासन ने थाना आसीवन में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में इन अभियुक्तों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई पांच अचल संपत्तियों को जब्त किया। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई है। जिलाधिकारी उन्नाव के आदेश और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में राजस्व विभाग, थाना आसीवन और थाना औरास पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर संपत्ति जब्तीकरण की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना आसीवन में दर्ज मुकदमा संख्या 20/2026, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत छह आरोपियों को नामजद किया गया था। इनमें राधेश्याम यादव (45), राम रहीश (52), अभिषेक यादव (23), मज्जन उर्फ कुलवंत (34), शेर सिंह उर्फ राजेश (50) (सभी निवासी नौगवां, थाना आसीवन) और अंकित उर्फ छुन्नू (23) (निवासी अरेर खुर्द, थाना आसीवन) शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने एक गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों से धन अर्जित किया था। इसी अवैध धन का उपयोग कर उन्होंने अपने और अपने परिजनों के नाम पर चल-अचल संपत्तियां बनाई थीं। प्रशासन द्वारा जब्त की गई कुल पांच भू-संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 56 लाख 5 हजार रुपये है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी और संबंधित पुलिस टीमें मौके पर मौजूद रहीं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। जांच के दौरान उनकी संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई।

शुक्लागंज में नवीन पुल निर्माण के लिए मकानों पर चला बुलडोजर, 10 भवन ध्वस्त

उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में बन रहे नवीन पुल की जद में आ रहे मकानों को गिराने का अभियान लगातार जारी है। राजस्व विभाग और सेतु निगम की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 10 मकानों को पोकलैंड मशीन से ध्वस्त किया जा चुका है। गुरुवार को भी इस अभियान के दौरान तीन मकानों को ढहा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि शेष मकानों को हटाने की कार्रवाई भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। मिश्रा कॉलोनी इलाके में नवीन पुल निर्माण के चलते कुल 38 मकान प्रभावित हो रहे थे। इन भवन स्वामियों को प्रशासन की ओर से पहले ही मुआवजे के चेक का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही मकान खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे। राजस्व विभाग की ओर से रविवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। शुरुआत में जेसीबी मशीन से मकानों को तोड़ने का काम कराया गया, लेकिन लगातार दो दिनों तक काम करने के बाद जेसीबी मशीन खराब हो गई। इसके बाद प्रशासन ने पोकलैंड मशीन लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। गुरुवार सुबह राजस्व विभाग के लेखपाल आशू श्रीवास्तव, फाजिल अंसारी और सेतु निगम के जेई कुंदन की मौजूदगी में तीन मकानों को गिराया गया। अधिकारियों के अनुसार, अब तक कुल 10 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि 28 मकान अभी शेष हैं। इन भवनों को हटाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रभावित भवन स्वामियों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं। लोग अपने घरों से गृहस्थी का सामान पहले ही दूसरी जगह ले जा चुके हैं। कई लोग मकानों के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य उपयोगी सामान भी अपने साथ ले जा रहे हैं।

उन्नाव में बीच सड़क भिड़ीं मौसी और भांजी, बाल खींचकर की मारपीट

यूपी के उन्नाव में मौसी और भांजी आपस में रोड पर भिड़ गईं। एक दूसरे को सड़क पर लिथार-लिथार कर पीटा, बाल नोंचे... गालियां दीं। उनके ब्वॉयफ्रेंड भी आपस में मारपीट कर रहे थे। मामला ये था कि मौसी और भांजी एक दूसरे के ब्वॉयफ्रेंड को मैसेज करती थीं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवतियों को शांत कराकर अलग किया। इसके बाद दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर राजधानी मार्ग पर गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र की है। घटना बुधवार रात की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में मौसी-भांजी मेन रोड पर एक दूसरे से मारपीट करते दिख रही हैं। पास में उनके ब्वॉयफ्रेंड भी लड़ते दिख रहे हैं। राहगीर तमाशबीन बने हुए हैं। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में राजधानी मार्ग स्थित सरस्वती टॉकीज के सामने बुधवार रात 9:30 बजे दो युवतियां आपस में बीच सड़क लड़ाई करने लगीं। विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। दोनों पक्षों की दो युवतियां और दो युवक आपस में भिड़ गए। युवतियों ने एक-दूसरे के बाल खींचे, जबकि युवकों के बीच भी हाथापाई हुई। सूचना मिलने पर गंगाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद विवाद शांत कराया। पुलिस ने दोनों युवतियों को घर भेज दिया, जबकि दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले आई।

जेल में बंद आरोपी की मौत का मामला

उन्नाव में धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में जेल भेजे गए एक कैदी की बुधवार को जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान सफीक अहमद के रूप में हुई है। मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के गेट के बाहर शव रखकर सड़क जाम कर दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे परिजन शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। यह मामला आसीवन थाना क्षेत्र का है। बेगम नगर रसूलाबाद निवासी शाहरुख अहमद ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 21 जून की दोपहर उनके छोटे भाई अनस पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। आरोप है कि नुरुल्लानगर निवासी आदिल और उसके पिता सफीक अहमद ने अनस को घर बुलाकर जान से मारने की नीयत से हमला किया। हमले में अनस के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। घायल अनस को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मियागंज और फिर जिला अस्पताल उन्नाव रेफर किया गया था। आसीवन पुलिस ने इस मामले में सफीक अहमद पुत्र मुन्ना निवासी नुरुल्लानगर को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर उसे जिला जेल भेजा गया था। बुधवार को जेल में सफीक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जेल कर्मी राजीव शुक्ला और सचिन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में डॉ. आशीष सिंह ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

उन्नाव में विभागीय कार्यों की समीक्षा, कई योजनाओं की प्रगति पर जताई चिंता

उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम ने बुधवार दोपहर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने और योजनाओं में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभागीय रैंकिंग, आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति और फैमिली आईडी सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम डैशबोर्ड में खनन, आबकारी, उपायुक्त उद्योग और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति खराब पाई गई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए। आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। केवल शिकायत का निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी आवश्यक है। असंतुष्टि स्तर बढ़ने पर उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों से धारा 34, 24, 116 और 38 से संबंधित लंबित वादों की तहसीलवार जानकारी मांगी। उन्होंने अभियान चलाकर लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।

परिवारवाद की राजनीति पर सीएम योगी का प्रहार, सपा-कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव पर पिता की विरासत के खिलाफ जाने का आरोप लगाया। उन्होंने दोनों दलों पर परिवारवाद, लोकतंत्र विरोधी रवैये और संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस गठबंधन पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव आज उस कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवार हैं, जिसका विरोध खुद उनके पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव आजीवन करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश अपने पिता की राजनीतिक विरासत को पूरी तरह मटियामेट करने पर उतारू हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस के पुराने इतिहास का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव के राजनीतिक आचरण पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने कहा, याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, तब मुलायम सिंह जी हमेशा उसका कड़ा विरोध करते थे। वह साफ कहते थे कि सब कुछ हो जाए, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी कोई समझौता या गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उनके उत्तराधिकारी (अखिलेश यादव) क्या कर रहे हैं? उनका आचरण देखिए, वे सिर्फ अपने फायदे के लिए मुलायम सिंह की विरासत को खुद ही डुबोने में लगे हैं।" मुख्यमंत्री ने दोनों दलों को घेरते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीति को बचाए रखने के लिए सपा और कांग्रेस एक साथ आए हैं। उन्होंने सपा के पिछले कार्यकालों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को कुचलने में इन दोनों दलों का इतिहास एक जैसा रहा है। संस्थाओं पर हमला : सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस (मीडिया) जैसी संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान नहीं किया जाता था और उन पर हमले किए जाते थे। संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत: उन्होंने आगे कहा कि ये लोग आज भी मिलकर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवारवाद को पोषित करना और संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत आचरण करना ये दल अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है। 'संविधान हत्या दिवस' के मौके पर दिए गए इस भाषण के जरिए भाजपा ने एक बार फिर सपा-कांग्रेस गठबंधन को घेरकर राज्य में नए राजनीतिक नैरेटिव को हवा दे दी है।

गाजियाबाद में चौंकाने वाला मामला: मृत समझे गए व्यक्ति की तेरहवीं में जिंदा वापसी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के वैशाली इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने परिवार, पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरत में डाल दिया। जिस व्यक्ति को परिवार मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर चुका था और जिसकी तेरहवीं का भोज चल रहा था, वह अचानक जिंदा घर लौट आया। वैशाली स्थित कल्पना अपार्टमेंट में बुधवार को 38 वर्षीय गिरधर सिंह बिष्ट की तेरहवीं का कार्यक्रम आयोजित था। परिजन और रिश्तेदार भोज में शामिल थे। इसी दौरान गिरधर सिंह अचानक सकुशल घर पहुंच गया। उसे सामने देखकर परिवार और मेहमानों के होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक, 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से विवाद के बाद कौशाम्बी थाना पुलिस ने गिरधर सिंह को शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर डासना जेल भेजा था। 21 मई को जेल से रिहा होने के बाद वह घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी बीच 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सूचना मिलने पर गिरधर के परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान गिरधर सिंह के रूप में कर दी। परिजनों की शिनाख्त के आधार पर पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिवार को सौंप दिया। शव मिलने के बाद परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, अगले दिन कौशाम्बी थाने पर हंगामा करते हुए परिजनों ने स्थानीय दुकानदारों पर गिरधर की हत्या का आरोप लगाया और मसूरी थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। लेकिन अब गिरधर के जिंदा लौट आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

भाजपा ने यूपी संगठन की नई कार्यकारिणी घोषित की

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा कर दी है। लंबे इंतजार के बाद जारी की गई नई प्रदेश कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अनुभवी नेताओं को भी संगठन में अहम पद देकर पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। बीजेपी की नई टीम में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ युवा नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है। नई प्रदेश कार्यकारिणी में सबसे अधिक चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर हो रही है। इसके अलावा पूजा पाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने इस बार संगठन में कई ऐसे चेहरों को जगह दी है, जिन्हें पार्टी के भविष्य के नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा की नई टीम में पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत 19 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी का मानना है कि इन नेताओं के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का लाभ आगामी चुनावों में मिलेगा। प्रदेश उपाध्यक्षों की नई टीम में विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे पार्टी के सामाजिक समीकरण और मजबूत होने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने नई कार्यकारिणी के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ा जाएगा।

मुजफ्फरनगर के मांडी गांव में बंधुआ मजदूरी कांड से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मांडी गांव में बंधुआ मजदूरी और उनके ऊपर हुए अमानवीय अत्याचार के मामले की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस क्रूरतापूर्ण घटना पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को सीधे तौर पर मानवीय गरिमा और भारतीय संविधान पर हमला बताया है। प्रियंका गांधी ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाए, जो भविष्य के लिए एक नजीर बन सके। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर आक्रोश जाहिर करते हुए लिखा- मुजफ्फरनगर से जो मामला सामने आया है, वह बेहद गंभीर और चिंता में डालने वाला है। प्रियंका ने कहा कि अगर देश के मजदूरों के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार किया गया है तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक बात है। यह सीधे तौर पर इंसानियत और हमारे संविधान के खिलाफ है। बंधुआ मजदूरी प्रकरण में जो खुलासे हुए हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आरोप है कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से लाए गए इन गरीब मजदूरों को उनके काम का कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। उन्हें अमानवीय हालात में बंधक बनाकर रखा गया था। मजदूरों को खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और मवेशियों का चारा दिया जाता था। हद तो तब हो गई जब खुलासा हुआ कि इन बेबस मजदूरों को कोड़े और धारदार हथियारों से पीटा जाता था और उन पर खूंखार पिटबुल कुत्ते छोड़े जाते थे। प्रियंका गांधी ने इस मामले में तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे देखकर भविष्य में कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने की हिम्मत न कर सके।